

बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आवास देगी राज्य सरकार

चर्चा में क्यों?

29 अक्टूबर, 2023 को बिहार सरकार द्वारा राज्य के 5 लाख शिक्षकों को आवास देने का नरिणय लया गया है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक लाख 22 हजार शिक्षकों का रजिलट जारी कया गया था।

प्रमुख बदि

- राज्य सरकार ने उन शिक्षकों के अलावा पहले से कार्परत् करीब 5 लाख शिक्षकों को आवास देने का नरिणय लया है। स्कूल के पास में ही रहने की व्यवस्था की जाएगी, ताका विद्यालय पहुँचने में लेट न हो।
- बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के आवास के लयि ज़िला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गाँव तक मकान को करिए पर लया जाएगा। इसके साथ ही रयिल एस्टेट कंपनी अगर मकान बनाकर देती है तो भी सरकार लेगी।
- शिक्षा वभाग ने इच्छुक मकान मालकों एवं रयिल एस्टेट कंपनयों से पूछा है कि कतिने फ्लैट और मकान तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं, साथ ही कतिने अगले एक-दो सालों में अतरिकित बनवा सकते हैं। इसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का नरिदेश दया गया है।
- शिक्षा वभाग प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के वेतन पर लगभग 33 हजार करोड़ रुपए खर्च करता है। इसमें 8 प्रतिशत, यानी लगभग 2500 रुपए करोड़ आवास के लयि खर्च कयि जाते हैं।
- शिक्षा वभाग के अनुसार आवास भत्ता की कटौती कर यह पैसा लीज़ पर लयि गए मकान और रयिल एस्टेट कंपनयों को दया जाएगा।
- शिक्षकों के दूरस्थ क्षेत्रों में आवास की सुवधि के लयि दो मॉडल पर शिक्षा वभाग कार्य कर रहा है, पहला मकान और बहुमंजलि इमारत के मालकों से प्रस्ताव मांगा गया है कि वह कतिने मकान कसि ज़िले में, कसि प्रखंड और ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा सकते हैं, जो पहले से बने हुए हैं। शिक्षा वभाग उसे करिए पर तुरंत ले सकता है।
- दूसरा-रयिल एस्टेट कंपनयों या अन्य इच्छुक ज़मीन मालकों से ज़िला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय में बहुमंजलि इमारत एवं भवन नरिमाण करने के लयि प्रस्ताव मांगा गया है। यहाँ केवल वभाग के शिक्षक रहेंगे। इन इमारतों को नजी कंपनयों अपने खर्चे पर बनाएंगी। शिक्षा वभाग उन्हें लंबे समय के लयि लीज़ पर लेगा और हर महीने करिया भुगतान करेगा।